

संख्या— /XXVIII(5)/2025 (E-61399)

प्रेषक,

डॉ० आर० राजेश कुमार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,  
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक अगस्त, 2025

विषय— Scheme For Special Assistance to State for Capital Expenditure 2025-26 Part-I के अन्तर्गत Govt. M.C. 100 Seated MBBS College Pithoragarh हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-318362/E-9061909(150)2020/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 जुलाई, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ के निर्माण कार्य हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 768.89 करोड़ के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक अवमुक्त ₹ 345.00 करोड़ को सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में Scheme For Special Assistance to State for Capital Expenditure 2025-26 Part-I (Untide) के अन्तर्गत Govt. M.C. 100 Seated MBBS College Pithoragarh हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अनुमोदित धनराशि ₹ 26.40 करोड़ (₹ छब्बीस करोड़ चालीस लाख मात्र) को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme For Special Assistance to State for Capital Expenditure 2025-26 Part-I (Untide) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
3. शासनादेश संख्या-285880/XXVIII(5)/2025 (E-83895) दिनांक 25 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

4. आगणन में सिविल कार्यों हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिड्यूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियाँ भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृति लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में शासन की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।
  5. आगणन में प्राविधानित नॉन शिड्यूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) एवं अद्यतन प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  6. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मद हेतु ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित कॉलेजों के प्राचार्य तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को होगा।
  7. उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017/ प्रोक्योरमेंट रूल, 2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  8. उक्त धनराशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक उपयोग करते हुए GFR 2017 के Form-12-B प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।
  9. उक्त धनराशि Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही है। अतः योजना की गार्डलाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग किया जाय।
- 2— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य भवन-26-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य (SASCI)-00- के मानक मद-53-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाले जायेगा।
- 3— शासनादेश संख्या-793/XXVIII(5)/2021-48(मे0का0)/2020 दिनांक 25 अगस्त, 2021 में उल्लिखित शर्त/प्रतिबन्ध भी यथावत् रहेंगी।

4— यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या-321940/2025 दिनांक 12 अगस्त, 2025 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

5— वित्त विभाग द्वारा निर्गत आई0डी0 संलग्न है।

**Digitally signed by  
Rajan Rajesh Kumar  
Date: 12-08-2025  
17:54:52**

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
4. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़।
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाइल।